

अर्नबका कहर

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की ताजा रिपोर्टके अनुसार चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ शुक्रवारको प्रातःकालसे अब समुद्रमें सक्रिय चक्रवात नहीं है, लेकिन इसके अवशेषोंसे पूर्वी और मध्य भारतमें वर्षाका दौर जारी है। २८ अक्तूबरकी अर्नबने आंध्रप्रदेशके नरसपुरके निकट तट पार किया था। तटसे टकराते समय यह अत्यन्त गम्भीर चक्रवाती तूफान था और हवाओंकी अधिकतम गति लगभग १२५-१३५ किलोमीटर प्रतिघण्टा रही, जबकि झोंकोंकी गति लगभग १५० किलोमीटर प्रतिघण्टातक पहुंची थी। २९ अक्तूबरको इसका अवशेष दक्षिण छत्तीसगढ़ और उससे लगे दक्षिण ओडिशाके ऊपर निम्न दबावके रूपमें रहा। इसके बावजूद अर्नबका प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है। ओडिशा और छत्तीसगढ़में ३१ अक्तूबरतक भारीसे बहुत भारी वर्षाकी आशंका जतायी गयी है। इसके अवशेषोंकी नश्वी उत्तरकी ओर पहुंचनेसे दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित उत्तर भारतके कुछ हिस्सोंमें वर्षा और हिमालयी क्षेत्रोंमें बर्फबारीकी स्थिति बनी हुई है। अर्नबसे प्रभावित राज्योंमें क्षति पहुंची है, लेकिन आंध्रप्रदेश और ओडिशामें व्यापक क्षति हुई है। पानी, बिजलीकी आपूर्ति तथा ट्रेन, बस और विमान सेवाएं काफी प्रभावित हुई हैं। १५ हजारसे अधिक बिजलीके खम्भे क्षतिग्रस्त हुए हैं। काफी संख्यामें पेंडु, मकान और फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी तैयारीका स्तर काफी अच्छा रहा जिससे जन-धनकी क्षति अपेक्षाकृत कम हुई है। लाखों लोगोंको सुरक्षित स्थानोंपर ले जाया गया। अर्नबके अवशेषोंके प्रभावकी आशंका पहले ही जता दी गयी थी। इनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार भी शामिल है। विश्वभरमें रिपोर्टोंको देखते हुए कहा जा सकता है कि चक्रवात अर्नब केवल मौसमी घटना नहीं है, बल्कि भारतकी आपदा-प्रबन्धन क्षमता, तटीय अर्थव्यवस्था और जलवायु-जोखिमके सन्दर्भमें महत्वपूर्ण घटनाके रूपमें देखा जाना चाहिए। अर्नबके कारण हुई वास्तविक क्षतिका आकलन अभी होना है। खेती, बागवानी, सड़क, पुलिया, राजमार्गोंको व्यापक नुकसान हुआ है। बिजली व्यवस्थाको विशेष क्षति पहुंची है। कितने लोगोंकी मृत्यु हुई है, इसका वास्तविक आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। तूफानका कृषि क्षेत्रपर सबसे बड़ा आर्थिक दबाव पड़ना स्वाभाविक है। अर्नबसे कृषि-आर्थिकीपर बड़ा झटका माना जाना चाहिए। पूर्वी भारतके कई क्षेत्रोंमें वर्षाका प्रभाव बना हुआ है। चक्रवातके पश्चात् सबसे बड़ी चुनौती उत्पन्न होने वाली है। केन्द्र और राज्य सरकारोंको मिलकर इस दिशामें कार्य करना होगा। क्षतिका वास्तविक आकलन शीघ्रतासे होना चाहिए।

एटीएसकी बड़ी सफलता

उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते (यूपी एटीएस) का फजी ई-मेल आईडी बनाने वाले नेटवर्कका पदोफाश करना, देशको अस्थिर करने वाली शक्तियोंपर अंकुश लगानेकी दिशामें महत्वपूर्ण सफलता मानी जायगी। इस सम्बन्धमें एटीएसने कानपुर नगरसे एक २४ वर्षीय युवकको गिरफ्तार किया है जिसके ई-मेल आईडीका इस्तेमाल नोएडा, दिल्ली-एनसीआर, गुरुग्राम और मुम्बईमें स्कूलों एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानोंको बमसे उड़ानेकी धमकी देनेके लिए किया गया था। इन धमकियोंमें सिंगर दिलजीत सिंह दोसांझके दिल्ली एनसीआरमें प्रस्तावित शो और बालीवुड अभिनेताके घरको निशाना बनानेकी धमकी भी शामिल है। खाम बात यह है कि इस गिरोहके जाल पाकिस्तान, बंगलादेश समेत अन्य देशोंतक फैला है। गिरफ्तार आरोपी वर्ष २०२१ से फजी ई-मेल आईडी बनानेका काम कर रहा था। उसके पाससे जो लैपटॉप बरामद किया गया है उसमें करीब पांच लाख ई-मेल आईडी मिले हैं, जो गम्भीर चिन्ताकी बात हैं। वह अपनी पहचान छिपानेके लिए वाई-फाई और प्राक्सी नेटवर्कका इस्तेमाल करता रहा। इन आईडीको सोशल मीडियाके फेसबुकसे जुड़े ग्रुप्सके जरिये बेच रहा था और बाइर्नेस क्रिटो वॉलेटके जरिये भुगतान लेता था। प्लूटलाछमें जो तथ्य सामने आये हैं वह चौंकाते बाले हैं। यह पूरा खेल अन्तरराष्ट्रीय स्तरपर संचालित था। पाकिस्तान, बंगलादेश समेत तुर्किये, मिस्र और अन्य देशोंके लोगों एवं समूहोंसे सम्पर्क भी सामने आये हैं, जो देशकी शान्ति, सुरक्षाके लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि उसके मोबाइलमें आतंकी समूहोंकी भी नाम हैं जिससे धमकीभरे सन्देश भेजे गये थे। इन सबकी महारानीसे जांच शुरू कर दी गयी है। देशविरोधी गतिविधियोंपर अंकुश लगानेके लिए यूपी एटीएसकी लगातार सक्रियता सराहनीय है। केन्द्रसे भी जानकारी साझा करनेकी जरूरत है, ताकि इन्हें समूल नष्ट किया जा सके।

लोक संवाद

राजनीतिके बदलते संकेत

महोदय,-उत्तर प्रदेशके विधान परिषद चुनावके परिणाम केवल कुछ सीटोंपर उम्मीदवारोंकी जीत और हारकी कसानी नहीं हैं, बल्कि इसके निहितार्थ बहुत गहरे हैं। २०२७ के विधानसभा चुनावसे पहले आये इन नतीजोंने प्रदेशकी राजनीतिमें नये खवाल खड़े कर दिये हैं। ११ विधान परिषद सीटोंके लिए हुए चुनावमें भारतीय जनता पार्टीने छह और समाजवादी पार्टीने पांच सीटें हासिल कीं। इन परिणामोंसे स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेशकी राजनीतिक जमीनपर सत्तापक्ष और विपक्षके बीच मुकाबला लगातार महत्वपूर्ण बना हुआ है। पहला निहितार्थ सत्तापक्षके लिए आत्मसंशयका है। भाजपने छह सीटें जीतकर अपना आधार बनाये रखा लेकिन वाराणसी और लखनऊ जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रोंमें मिली पराजयने राजनीतिक विस्फोणकी नयी गुंजाइश पैदा की है। विशेष रूपसे वाराणसी प्रथम मंत्री नरेन्द्र मोदीका संसदीय क्षेत्र है। यहां समाजवादी पार्टीकी सफलताको केवल एक सीटकी जीत मानकर नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। हालांकि विधान परिषदके चुनावका मतदाता वर्ग विधानसभा चुनावसे अलग होता है इसलिए इन परिणामोंकी पूरे प्रदेशकी जन-भाषाका सीधा प्रतिबिम्ब मानना उचित नहीं होगा। दूसरा निहितार्थ विपक्षके मनोबलसे जुड़ा है। समाजवादी पार्टीने पांच सीटें जीतकर यह संकेत दिया है कि वह अपने संघटन और समर्थक वर्गके बीच सक्रिय राजनीतिक उपस्थिति बनाये हुए है। विपक्षके लिए यह परिणाम आगामी विधानसभा चुनावकी तैयारियोंकी गति देनेका अवसर बन सकता है। लेकिन विधान परिषदमें मिली सफलताको विधानसभा चुनावमें जीतकी राहकी समझना भी राजनीतिक भूल होगी। तीसरा निहितार्थ शिक्षकों और छात्रोंके बीच है। विधान परिषदकी इन सीटोंपर शिक्षक और छात्रक मतदाता अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं। शिक्षाकी गुणवत्ता शिक्षकोंकी समस्याएं रोजगारके अवसर विश्वविद्यालयोंकी स्थिति और युवाओंके भावि्य जैसे मुद्दे इस चुनावके व्यापक संदर्भका हिस्सा हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियोंके सामने अब चुनौती होगी कि वे इन वर्गोंकी अपेक्षाओंको सदर्थमें प्रभावी ढंगसे उठायें। चौथा निहितार्थ संघटनात्मक क्षमता और स्थानीय नेतृत्वसे जुड़ा है। चुनाव परिणाम बताते हैं कि स्थानीय स्तरपर उम्मीदवारोंकी स्वीकार्यता संघटनकी सक्रियता और मतदाताओंसे संपर्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केवल बड़े नेताओंके प्रभावके भरोसे चुनावी सफलता सुनिश्चित नहीं की जा सकती। राजनीतिक दलोंकी स्थानीय समस्याओं और मतदाताओंकी अपेक्षाओंको समझना होगा। पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण निहितार्थ २०२७ के विधानसभा चुनावकी प्रथम मंत्री चुनूा है। इन नतीजोंसे भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनोंकी अपनी राजनीतिक तैयारियोंकी समीक्षा करनेका अवसर मिला है। भाजपाके सामने अपने समर्थन आधारको मजबूत बनाये रखनेकी चुनौती है जबकि समाजवादी पार्टीके सामने इस सफलताको व्यापक जनसंपर्क और संघटनात्मक मजबूतीमें बदलनेका प्रश्न है। अंततः एमएलएस चुनावके नतीजोंको न तो सत्तापक्षके लिए अंतिम चेतावनी मानना चाहिए और न ही विपक्षके लिए आगामी विजयका प्रमाण। लोकतंत्रमें प्रत्येक चुनाव अपने साथ कुछ संदेश लेकर आता है। इन संदेशोंका सतर्क निरीक्षण और विश्लेषण आवश्यक है। उत्तर प्रदेशकी राजनीतिमें इन परिणामोंकी अपेक्षाओंकी कितनी गम्भीरतासे समझते हैं और उन्हें पूरा करनेके लिए क्या कदम उठाते हैं।-**सूर्यदीप कुमारवाहा, वाराणसी।**

ट्रम्पसे असंतुष्ट अमेरिकी मतदाता

लगभग ६८ प्रतिशत मतदाता ट्रम्पके कामकाजसे और ७१ प्रतिशत उनकी आर्थिक नीतियोंसे असंतुष्ट हैं। युवा वर्ग और विभिन्न जातीय अल्पसंख्यकोंमें ट्रम्पके प्रति कड़ी नाराजगी देखी गयी है। अमेरिकाका मध्यवर्ग पेट्रोलियम पदार्थों, गैस, भोजन और जीवनयापनकी बढ़ती लागतको लेकर ट्रम्पको कोसना शुरू कर चुका है।

□ पुष्परंजन

अमेरिकी मध्यावधि चुनावका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मतदान ३ नवंबरको है। ट्रम्प मध्यावधि चुनाव हार भी जाते हैं, फिर भी उनको कुर्सी आसानीसे नहीं जायगी। ट्रम्पने खुद आशंका जतायी है कि यदि डेमोक्रेटस कांग्रेसपर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं तो वे उनपर महाभियोग चलानेकी कोशिश कर सकते हैं। यदि डेमोक्रेटिक पार्टी प्रतिनिधि सभा या सीनेटमें बहुमत पा लेते है तो ट्रम्पके लिए बजट या नीतिवां पास कराना बेहद मुश्किल हो जायगा। हालांकि उनके पास वोटोंकी शक्ति होगी, जिसका इस्तेमाल वे किसी भी बिलको रोकनेके लिए कर सकते हैं। बहुमत खोनेकी स्थितिमें विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ट्रम्प प्रशासनकी नीतियोंकी संसदीय जांच शुरू कर सकती है, जिससे उनकी राजनीतिक मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज भी अर्थाईडक्स यहूदी समुदायके लगभग ७० प्रतिशतसे अधिक मतदाता डीनारल्ड ट्रम्प और रिपब्लिकन पार्टीका खुलकर समर्थन करते हैं। इनका मिजाज बदलता नहीं दिख रहा। लेकिन जो बदल रहे हैं, वे हैं ब्लैक, हिस्पैनिक, यहूदी, मुस्लिम, हाइट वकिंग-क्लास और इवैजेलिकल मतदाता। २०२४ में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चुननेमें इनका बड़ा योगदान था। रिवनर वोटसंका अब ट्रम्प प्रशासनसे मोहभंग हुआ है। ट्रम्प अगुमन अमेरिका फर्स्ट और नेशनल इंटररेट जैसे शब्द इस्तेमाल करते रहे। लेकिन जब परिवारके बजटपर दबाव पड़ता है तो ये टोटके बकबास लगने लगते हैं।

ट्रम्प यदि मध्यावधि चुनाव जीत गये, तब तो मानकर चलिए, तेहरानकी खैर नहीं होगी। अगले दो वर्षोंतक ट्रम्प ईरान जैसे कुछ और युद्ध वाले इलाके सुवित कर लेंगे। सत्तारूढ़ रिपब्लिकन पार्टीका संसदके दोनों सदनों (प्रतिनिधि सभा और सीनेट) पर नियंत्रण बना रहेगा, जिससे ट्रम्प अपने एजेंडें, टैक्स सुधारों और नीतियोंको आसानोसे आगे बढा सकेंगे। ट्रम्पपर महाभियोग चलाने की संभावना काफी कम हो जायगी। जीत गये तो वादेके अनुसार २७ करोड़ १५ लाख अमेरिकी वयस्कोंकी ५,००० होलारका चेक देना पड़ेगा। इससे सरकारी खजानेपर अतिरिक्त बोझ पड़ना तय है।हालांका सर्वेक्षणोंपर यकीन करें तो लगभग ८७ प्रतिशत डेमोक्रेटिक मतदाता ट्रम्पके कामकाज और उनकी आर्थिक नीतियोंसे

असंतुष्ट हैं। करीब ७२ प्रतिशत अश्वेत मतदाता ट्रम्पके कुल कामकाजको नापसंद करते हैं। राष्ट्रीय स्तरपर स्वतंत्र मतदाताओंका एक बड़ा हिस्सा ट्रम्पसे निराश है। लगभग ६८ प्रतिशत स्वतंत्र मतदाता ट्रम्पके कामकाजसे और ७१ प्रतिशत उनकी आर्थिक नीतियोंसे असंतुष्ट हैं। जैन-जो श्रेणीके युवा वर्ग और विभिन्न जातीय अल्पसंख्यकोंमें ट्रम्पके प्रति कड़ी नाराजगी देखी गयी है। अमेरिकाका मध्यवर्ग पेट्रोलियम पदार्थों, गैस, भोजन और जीवनयापनकी बढ़ती लागतको लेकर ट्रम्पको कोसना शुरू कर चुका है।

एशियाई अमेरिकी और पैसिफिक आइलैंडर (एएपीआई) मतदाता अमेरिकी मतदाताओंके सबसे विविध समूहोंमें से एक हैं।'आपी' मतदाताओंका वर्ग सबसे तेजीसे बढ़ रहा है।एएपीआई (आपी) समुदायमें लगभग १.७ करोड़ वयस् मतदाता हैं, जिनमेंसे ५६ प्रतिशतने २०२४ में अपना वोट डाला था।द एसोसिएटेड प्रेस-नॉर्क सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स रिसर्च (एपी-नॉर्क-एएपीआई) के एक नये पोलेके अनुसार ३ नवंबरके मध्यावधि चुनावोंके करीब आते-आते एशियाई अमेरिकी, मूल हवाईयन और प्रशंत द्वीपवासी रिपब्लिकन पार्टीसे और अधिक निराश हो गये हैं।एपी-नॉर्क-एएपीआई द्वारा ८ से १५ सितंबर २०२६ के बीच किये गये सर्वेक्षणसे पता चलता है कि ट्रम्पके दूसरे

कार्यकालके दौरान अर्थव्यवस्थाको लेकर उनकी छवि खराब हुई है। इन वयस्कोंमेंसे लगभग एक-तीथाई लोग हो राष्ट्रपतिके रूपमें ट्रम्पके कामकाजके तरीकेको पसंद करते हैं। अर्थव्यवस्थाके मोर्चेपर उनके प्रदर्शनको केवल दस मेंसे दो लोग ही सही मानते हैं, जबकि एएपीआई समूहके अधिकांश वयस्क इसे आगामी चुनावोंके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दोंमेंसे एक मानते हैं।आयीवके कॉर्निंगमें रहने वाली ७५ वर्षीय कोरियाई अमेरिकी रेबेका जारोकोने २०२६ में ट्रम्पको बोट दिया था, लेकिन अर्थव्यवस्थाकी संभालनेके उनके तरीकेको लेकर अधश्न नहीं हैं, खासकर ऐसे समयोंकबे ईरान युद्धके कारण पेट्रोल-डीजलकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। पिछले तीन प्रेसिडेंशियल माइकिलमें लगभग ६,२०,००० नये मतदाता बने, जिनमें कैलिफोर्निया, हवाई, इलिनोइस, मैसाचुसेट्स,

संघटनात्मक आत्ममंथनका अवसर

बैलेट पेपरसे चुनाव करानेपर मतदानका माध्यम बदला, लेकिन लोकतंत्रकी मूल कसौटियां नहीं बदलीं। मतदाता का विश्वास, निष्पक्ष प्रतियस्पर्धा, पारदर्शी मतगणना और परिणामोंकी विश्वसनीयता आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं।

□ महेन्द्र तिवारी

पिछले कुछ समयसे इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनोंको विश्वसनीयताको लेकर राजनीतिक बहस चल रही है। विपक्षके कई नेता बैलेट पेपरसे चुनाव करानेकी मांग करते हैं। ऐमेंमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटकमें विधान परिषदकी २८ सीटोंके लिए बैलेट पेपरसे हुए चुनावोंने एक बार फिर इस बहसको जेन कर दिया है। सवाल यह है कि बैलेट पेपरसे चुनाव करानेपर आछिर क्या बदला। क्या इससे चुनावी व्यवस्थाकी विश्वसनीयता मायित हुई। २३ अक्तूबर २०२६ को चार राज्योंमें विधान परिषदकी शिक्षक और छात्रक निर्वाचन क्षेत्रोंकी सीटोंके लिए मतदान हुआ। इन चुनावोंने इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनोंके स्थानपर मतपत्रोंका इस्तेमाल किया गया। मतगणनाके दौरान भाजपा और उसके सहयोगियोंमें कई सीटोंपर सफलता प्राप्त की। सभने उत्तर प्रदेशमें अपनी उपस्थिति मजबूत की, जबकि बिहारमें जन सुराज पार्टीने भी विधान परिषदमें अपना खाता खोला। कांग्रेसको बुरुआती परिणामोंमें किसी सीटपर सफलता नहीं मिली। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीने इसी स्थितिका उल्लेख करते हुए कांग्रेसपर राजनीतिक टिप्पणी की और खवाल किया कि बैलेट पेपरसे हुए चुनावोंमें पार्टी कितनी सौटें जीत पायी। इस टिप्पणोने मतदान प्रणालीको लेकर चल रही बहसको फिर चर्चामें ला दिया। हालांकि अंतिम परिणामोने इस राजनीतिक चर्चाको एक नया मोड़ दिया। महाराष्ट्रके नागपुर छात्रक निर्वाचन क्षेत्रमें कांग्रेसके अभिजीत वंजारीने भाजपाके सुभाकर कोहलेंको ३२७१ मतोंसे पराजित कर दिया। इस सीटपर मतगणना लम्बी चली और दूसरी बरीयतके मतोंकी गणनाके बाद परिणाम सामने आया। नागपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघका मुख्यालय होनेके साथ महाराष्ट्रके मुख्य मंत्री देवेन्द्र फडणवीस और केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरीका गुरुक्षेत्र भी है। ऐसे क्षेत्रमें कांग्रेसकी जीतने भाजपाके लिए राजनीतिक चुनौती खड़ी की। इससे स्पष्ट होता है कि चुनावके बुरुआती रझाओं और अंतिम परिणामोंमें अन्तर हो सकता है। इन चुनावोंसे पहला बदलाव मतदानके तरीकेमें दिखाई दिया। इलेक्ट्रॉनिक मशीनोंके स्थानपर मतपत्रोंका उपयोग किया गया। लेकिन केवल मतगणना माध्यम बदलनेसे मतदाताओंकी राजनीतिक पसंद नहीं बदल जाती। मतदाता किसी उम्मीदवारको उसकी लोकप्रियता, राजनीतिक विचारधारा, स्थानीय कामकाज, संघटनकी सक्रियता और अपनी समस्याओंके समाधानकी उम्मीदोंपर समर्थन प्रचुरते हैं। इस दृष्टिसे बैलेट पेपरसे हुए चुनावोंने यह नहीं बताया कि कौन-सी मतदान प्रणाली राजनीतिक दलोंको अधिक सौटें दिलाती है। उन्होंने केवल यह दिखाया कि मतपत्रोंसे मतदान होनेपर भी राजनीतिक प्रतियस्पर्धा और उम्मीदवारोंकी क्षमता महत्वपूर्ण बने रहते हैं। दूसरा बदलाव राजनीतिक बहसमें दिखाई दिया। विपक्ष लम्बे समयसे इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनोंकी विश्वसनीयतापर सवाल उठाता रहा है। ऐमेंमें बैलेट पेपरसे हुए चुनावोंके परिणामोंकी भावपाने विश्वासकी दलीलोंके जवाबके रूपमें प्रस्तुत किया। उनका कतं रहा कि जब मतपत्रोंसे चुनाव हुए, तब भी कांड़सको अप्रतिक्ष सफलता नहीं मिली। दूसरी ओर विपक्ष यह कह सकता है कि विधान परिषदके सीमित निर्वाचन क्षेत्रोंके परिणामोंकी तुलना लोकसभा और विधानसभा चुनावोंसे सीधे नहीं की जा सकती। दोनों पक्षोंकी

हादसोंपर लगाम लगायेगी आधुनिक तकनीक

□ अली खान

एईबीएसका सबसे बड़ा प्रभाव यह होगा कि यह मानव भूलके कारण होने वाले गम्भीर हादसों और उनसे होने वाली मौतोंकी संख्यामें भारी कमी लायेगा। इसके लागू होनेसे न केवल कारोंमें बैठे यात्रियोंकी जान सुरक्षित होगी, बल्कि पैदल चलने वाली और दोपहिया सवारीकी भी सुरक्षा मिलेगी। सड़क हादसोंमें लगातार बढ़ती मौतों और घातक दुर्घटनाओंपर लगाम लगानेके उद्देश्यसे भारत सरकारने एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम उठाया है। केन्द्र सरकारके सड़क परिवहन मंत्रालयने प्रस्ताव पारित किया है कि अक्टूबर २०३० से देशमें बनने वाले सभी नये कार मॉडलोंमें ‘एडवांस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम’ की अनिवार्य रूपसे लागू किया जायगा। अबतक केवल महंगी और लक्जरी कारोंतक सीमित रहने वाली यह प्रौमियम सुरक्षा तकनीक अब आम बजटकी चार पहिया गाड़ियोंका भी हिस्सा बनेगी। नये नियमोंके द्वाप्ट नोटिफिकेशनके मुताबिक १ अक्टूबर, २०३० या उसके बाद आने वाले एम१ श्रेणीके सभी नये कार मॉडलोंमें एईबीएसका होना अनिवार्य होगा।

इसके अलावा जो मौजूदा कार मॉडल इस समय-सीमाके बाद भी बनते रहेंगे, उन्हें यह तकनीक अपनानेके लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। और उनके लिए यह नियम अक्टूबर, २०३२ से प्रभावी होगा। सरकारने केवल कारों ही नहीं, बल्कि मध्यम और भारी व्यावसायिक वाहनोंके लिए भी कड़े नियम तय किये हैं, जिसके तहत १ अक्टूबर, २०२७ से ट्रकोंके लिए संशोधित ब्रेकिंग

जो सज्जनताका अतिक्रमण करता है उसकी आयु, संपत्ति, वश, धर्म, पुण्य, आशीष, श्रेय सभी कुछ नष्ट हो जाते हैं।

विदुर नीति

मिमेंसोट, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, नेबदा, ओरेगन, वर्जीनिया, टेक्सास और वाशिंगटन जैसे राज्योंमें इनको ताकत बढ़ी या यूं कहें कि पांच पैसेसी नये आपी मतदाता नये ताकत बने। ट्रम्पने शुरूमें अपने स्तरपर कुछ प्रमुख पदोंपर आपी समूहके व्यक्तियों (जैसे-तुलसी गबाई, काश पटेल) को नियुक्त किया था। लेकिन यह बहुत टिकाऊ साबित नहीं हुआ। तुलसी गबाईने स्वयं २२ मई, २०२६ को राष्ट्रीय खुफिया निदेशकके पदसे इस्तीफा दिया था। उन्होंने इस्तीफेको मुख्य वजह अपने पति अब्राहम विलियम्सका वोन कैसर्स पीड्रॉत होना बताया थी, जिसके चलते वह अपने परिवारके साथ रहना चाहती थीं। रिपोर्टोंमें यह भी कहा गया था कि ईरान नीति और विदेशी मामलोंपर उनके डोनाल्ड ट्रम्पसे मतभेद थे और उन्हें बड़े फैसलोंसे दूरकियन किया जा रहा था। काश पटेल अब भी एफबीआईके निदेशकके पदपर बने हुए हैं। हालांकि अप्रैल २०२६ में उनकी कार्यशैली, शराबको लत और अनुपस्थितिको लेकर द अटलांटिककी एक रिपोर्टके बाद उनके इस्तीफे या हटाने जानेकी अटकलें जरूर तेज हुई थीं। फिर भी, काश पटेलको ट्रम्पने तो-प्राफाइलमें रखा है। यह जगवाहिर है कि ट्रम्प और प्रधान मंत्री मोदीके ‘माई डियर फ्रेंड’ वाले रिसे सख्त नहीं रहे। २२ सितंबर २०२९ को ब्लूट्स्के एनआरजी स्टैंडियममें आयोजित ‘हाउडी मोदी’ जैसे मेगा इवेंटका

इतिहास दोहराया नहीं जा सका। रूससे लगातार कच्चा तेल खरीदना भी दोनों नेताओंके बीच अनबनकी एक बड़ी वजह बनी। भारत-पाकिस्तानके बीच युद्धविमान करानेकी दावेदारी और एमएटीन फाउलस जैसे विवाचित विषयोंकी उठाकर ट्रम्प

प्रधान मंत्री मोदीपर मानसिक दबाव बनाते रहे।

भारत-अमेरिका व्यापार संधिको ट्रम्प प्रशासनने अत्यधिक जटिल बना रखा है। ट्रम्प प्रशासनकी ओरसे समय-समयपर टैरिफ दरें और शर्तोंमें बदलाव (जैसे- दस प्रतिशत, १५ प्रतिशत, १९ प्रतिशत या २५ प्रतिशत तकके जवाबी शुल्कका मुद्दा) से दोनों पक्षोंके बीच भरोसा कायम करनेमें चुनौतियां आयी हैं। अब ट्रम्प मध्यावधि चुनावमें जीतें या हारें, उससे पीएम मोदीको क्या खरना है बल्कि ट्रम्प यदि हारते हैं तो मोदीपर उनके प्रहारकी धार कम हो जायगी। आप २०२० का मंत्र यह थाद फ्रीड। ट्रम्पकी जीतके लिए भारतमें चुनावीयों और हिन्दू समूहों द्वारा विशेष पूजा-अर्चना, हवन और महायज्ञ किये गये थे। सवाल है अब ये हिन्दू संघटन ट्रम्पके लिए पूजा-पाठ, हवन इत्यादि क्यों नहीं करवा रहे।



प्रेम भावसे प्रार्थना

□ ओशो

प्रेम यदि पाप है तो पुण्य असंभव है। क्योंकि पुण्यका सार प्रेमके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। तथाकथित साधु, महात्मा यही कहते हैं कि प्रेम पाप है और वह ऐसी वस्तुओं बात कहते रहे हैं, लेकिन इन्होंने इतने लंबे अरसेसे कही है कि उसकी व्यर्थता, उसका विरोधाभास दिखाई नहीं पड़ता। प्रेमको तो वह पाप कहते हैं और प्रार्थनाको पुण्य कहते हैं और तुमने कभी गौरसे नहीं देखा कि यदि प्रेम पाप है तो प्रार्थना भी पाप हो जायगी। क्योंकि प्रार्थना प्रेमका ही परिशुद्ध रूप है। घना कि प्रेममें कुछ अशुद्धियां हैं, लेकिन पाप नहीं है। सोना यदि अशुद्ध हो तो भी लोहा नहीं है। सोना अशुद्ध हो तो भी सोना है। अशुद्ध होकर भी सोना, सोना है। रही शुद्ध करनेकी बात, सो शुद्ध कर लेंगे। कूड़े, कंकटको जला देंगे, सोनेको आगसे गुजार लेंगे, जो व्यर्थ है जल जायगा आगमें, जो सार है, जो शुद्ध है बच जायगा। प्रेम और प्रार्थनामें उलना हो फर्क है जितना अशुद्ध सोने और शुद्ध सोनेमें। परन्तु दोनों ही सोना हैं। अतीतने प्रार्थना और प्रेमको अलग-अलग तोड़ दिया था और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि प्रेम कलुषित हो गया। एक तरफ प्रेमको अपराध बना दिया तो जो प्रेममें थे, उनको आत्मका अपमान किया, उनके भीतर आत्मनिंदा पैदा कर दी और इन बातोंमें इससे बड़ी कोई दुर्घटना नहीं है कि किसी व्यक्तिके भीतर आत्मनिंदा पैदा हो जाए। प्रेम पाप है तो जो भी प्रेम करते हैं, सब पापी हैं और कौन है जो प्रेम नहीं करता। कोई पत्नीको करता है, कोई पतिको, कोई बेटेको, कोई भाईको, कोई मित्रको। शिथ भी तो ट्रकोंको प्रेम करते हैं। गुरु भी शिष्योंको प्रेम करता है। यहां जितने संबंध हैं, वह सार संबंध मात्र प्रेमके हैं। हमने प्रेमको पापी कर दिया। सारा संसार हमने पापसे भर दिया, एक छोटी-सी भूल करके कि प्रेम पाप है। दूसरा दुष्परिणाम हुआ है कि जब प्रेम पाप हो गया तो प्रार्थना हमारी बोधी हो गयी, उसमें प्राण प रहे, औपचारिक हो गयी। प्राण तो प्रेम्से मिल सकते थे तो प्रेमको तो हमने पाप कर दिया। जीवन तो प्रेम्से मिलता है। प्रार्थनाके द्वार बंद कर दिये। प्रेमको ही भूमिसे प्रार्थना रम पाती है तो हमने भूमिकी निंदित कर दिया और प्रार्थनाके वृक्षको भूमिसे अलग कर लिया। भूमि वृक्षहोती हो गयी और वृक्ष मुर्दा हो गया। मैं घोषणा करता हूं कि प्रेम पुण्य है। विस्वकी अगिसे गुंजारो इसे और तुम धीरे-धीरे पाओगे कि तुम्हारे हाथोंमें प्रार्थनाका पत्थी लग गया है, जिसके पंज हैं, जो आकाशमें फैल गये हैं। जो इतना हल्का है। क्योंकि सारा बोझ कर गया, सारी व्यर्थता गिर गयी। जिस दिन प्रार्थनाको अनुभव कर पाओगे, इस दिन तुम भगवद्वद दोगे अपने सारे प्रेमके संबंधोंको, क्योंकि उनके बिना तुम प्रार्थनातक कभी नहीं आ सकते थे। प्रेम जब प्रार्थना बनता है तो परमात्माके द्वार खुलते हैं। अपने अंतःकरणमें उस परमात्माको बसा कर सच्चे हृदयसे की गयी प्रार्थना हमेशा सफल होती है।

मानक और इलेक्ट्रॉनिक स्टैबिलिटी कंट्रोल सिस्टमकी अनिवार्य कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि एडवांस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम एक अत्याधिक आधुनिक और एआई-संचालित एक्टिव सेफ्टी तकनीक है, जो सड़कपर आगे चल रहे वाहनों, पैदल यात्रियों या अचानक आयी किसी बाधाको रियल-टाइममें ट्रैक करती है। यह सिस्टम गाड़ीके अगले हिस्सेमें लगे उच्च क्षमता वाले रडार, लिडर सेंसर और कैमरोंका उपयोग करके लगातार सामनेके ट्रैफिक और दूरीका विश्लेषण करता रहता है। जब कोई दूसरा वाहन या बाधा अचानक गाड़ीके सामने आ जाती है और चालक द्वारा समयपर कोई प्रतिक्रिया (जैसे ब्रेक लगाना या स्टेर्योस मोड़ना) नहीं दी जाती तो एईबीएस तुरन्त एक्टिव हो जाता है। यह सिस्टम पहले चालतको डैशबोर्डपर विब्रान्त लाइट और अलर्ट साउंड्सके जरिये चेतावनी देता है। यदि चालक इसके बावजू भी कोई त्वरित प्रतिक्रिया नहीं देता है तो सिस्टम वाहनके अर्नि-नॉड कम्प्यूटरको सन्देश भेजकर ऑटोमैटिकली इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक चालू कर देता है। यह पूरी प्रक्रिया एक सेकंडके भी छोटे हिस्सेमें पूरी हो जाती है, जिससे तेज रफ्तार गाड़ी समय रहते रुक जाती है या उसकी गति इतनी कम हो जाती है कि टकरानेका जोखिम न के बराबर रह जाता है।

यदि हम सड़क सुरक्षा और भारतीय यातायातपर एईबीएसके दूरगामी प्रभावकी बात करें तो भारतीय सड़कोंपर एईबीएस और ट्रकोंमें इलेक्ट्रॉनिक स्टैबिलिटी कंट्रोल लागू होनेसे देशके ऑटोमोटािव सेक्टर और सड़क सुरक्षा परिदृश्यपर सकारात्मक और क्रांतिकारी प्रभाव देखनेको मिलेगा। सड़क हादसोंके आंकड़ोंपर नजर डालें तो एक बड़ी संख्यामें दुर्घटनाएं झूझवर्की

भारत सरकारका यह फैसला देशको वैश्विक सड़क सुरक्षा मानकोंके समतुल्य खड़ा करता है। यद्यपि शुरुआतमें कार और ट्रक निर्माताओंके लिए इन उन्नत तकनीकोंको अपनने बेश मॉडलोंमें एकीकृत करना लागतके दृष्टिकोणसे एक चुनौती हो सकता है, लेकिन समयके साथ बड़े पैमानेपर उत्पादन होनेसे एईबीएस तकनीक काफी सस्ती और सुलभ हो जायगी। यह नीति न केवल कार खरीदारोंमें सुरक्षाके प्रति जागरूकता बढ़ायेगी, बल्कि भारतके ऑटोमोबाइल बाजारकी अधिक सुरक्षित और तकनीक-संपन्न बनायेगी। एईबीएस जैसे फीसर्त तकनीक और मानवीय जीवनकी सुरक्षाका एक बेहतरीन संतुलन पेश करते हैं, जो आने वाले दशकोंमें भारतीय सड़कोंको सभी के लिए सुरक्षित, सुगम और दुर्घटना-मुक्त बनानेमें मौलका पथर साबित होंगे।